



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (II)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 132]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 27, 1981/चैत्र 6, 1903

No. 132]

NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 27, 1981/CHAITRA 6, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

उद्योग मंत्रालय
(औद्योगिक विकास विभाग)

वधिसूचना

नई दिल्ली, 27 मार्च, 1981

का०अ० 228 (अ).—केन्द्रीय सरकार, हिंद साइकिल्स लिमिटेड और सैन-रेले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 70) की धारा 31 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिंद साइकिल्स लिमिटेड और सैन-रेले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) नियम, 1981 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं:—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “अधिनियम” से हिंद साइकिल्स लिमिटेड और सैन-रेले लिमिटेड (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1980 (1980 का 70) अभिप्रेत है;

(ख) “धारा” से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

3. सूचना के लिए समय-सीमा :—किसी ऐसी संपत्ति का जो, यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या किसी सरकारी कंपनी के अधिनियम के

अधीन निहित हो गई है, प्रत्येक बंधकदार, और किसी ऐसी सम्पत्ति में या उसके संबंध में कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला प्रत्येक व्यक्ति ऐसी तारीख से जो केन्द्रीय सरकार अधिनियम की धारा 18 के अधीन विनिर्दिष्ट करे, तीस दिन की अवधि के भीतर, ऐसे बंधक, भार, धारणाधिकार या अन्य हित की सूचना प्रायुक्त को देगा :

परन्तु यदि प्रायुक्त का यह समाधान हो जाता है कि बंधकदार या कोई भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाला व्यक्ति, पर्याप्त कारणों से उक्त तीस दिन की अवधि के भीतर सूचना देने से निवारित हो गया था तो प्रायुक्त कारणों को लेख बद्ध करके, तीस दिनों की प्रतिरिक्त अवधि के भीतर सूचना से सकेगा उसके पश्चात् नहीं।

4. सूचना की रीति :—(1) नियम 3 के अधीन प्रायुक्त को दी जाने वाली प्रत्येक सूचना, लेखबद्ध रूप में, प्रायुक्त के नाम से, भेजी जाएगी और उसमें निम्नलिखित विनिर्दिष्टियां होगी, अर्थात् :—

(क) बंधकदार/किसी भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति का नाम, वर्णन और पूरा पता :

(ख) उस उपक्रम का नाम, जिसकी वाबत दावा किया गया है;

(ग) ऐसे दावे की रकम (भारतीय करेसी में);

(घ) ऐसी लिखत की, यदि कोई है, विनिर्दिष्टियों, जिससे ऐसा बंधक भार, धारणाधिकार या अन्य हित प्रतिभूत किया गया है, जिसका समर्थन लिखत की प्रमाणित प्रत से किया जाएगा...

- (इ) रकम, यदि कोई है, जो पहले ही प्राप्त की गई है, और उसकी विधिद्वारा ;
- (च) ऐसे ऋण से सुसंगत कोई अन्य विधिद्वारा ;
- (छ) अनुलोप, जिसका दावा किया गया है।
- (2) प्रत्येक सूचना, बंधकदार या ऐसा भार, धारणाधिकार या अन्य हित धारण करने वाले व्यक्ति या ऐसे व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर की जाएगी, और सत्यापित की जाएगी।
- (3) सूचना, आयुक्त के कलकत्ता या मुम्बई स्थित कार्यालय में, सभी कार्य दिवसों में, कार्यालय के समय के दौरान फाइल की जाएगी या आयुक्त को खोली रजिस्ट्री डाक द्वारा भेजी जाएगी।

[फा० सं० आई एम ई-49(10)81]

मनोस बहल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Industrial Development)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th March, 1981

S.O. 228(E).—In exercise of the powers conferred by section 31 of the Hind Cycles Limited and Sen-Raleigh Limited (Nationalisation) Act, 1980 (70 of 1980), the Central Government hereby makes the following rules namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Hind Cycles Limited and Sen-Raleigh Ltd. (Nationalisation) Rules, 1981.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules, unless the context otherwise requires :—

(a) "Act" means the Hind Cycles Limited and Sen-Raleigh Limited (Nationalisation) Act, 1980.

(b) "section" means a section of the Act.

3. Time-limit for intimation.—Every mortgagee of any property which has vested under the Act in the Central Government or in a Government Company, as the case may be, and every person holding any charge, lien or other interest in, or in relation to, any such property shall give intimation of such mortgage, charge, lien, or other interest to the Commissioner within a period of thirty days from such date, as may be specified by the Central Government under section 18 :

Provided that if the Commissioner is satisfied that the mortgagee of the person holding any charge, lien or other interest was prevented by sufficient cause from giving the intimation within the said period of thirty days, he may, after recording reasons in writing receive the intimation within a further period of thirty days and not thereafter.

4. Manner of intimation.—(1) Every intimation to be given to the Commissioner under rule 3 shall be in writing addressed to the Commissioner, and shall contain the following particulars, namely :—

- Name, description and full address of the mortgagee/charge, lien or other interest holder ;
- Name of the undertaking in respect of which the claim is made ;
- amount of claim (in Indian currency) ;
- particulars of the instrument, if any, by which the mortgage, charge, lien or other interest is secured, supported by an attested copy of the instrument ;
- amount, if any, already received, with particulars ;
- any other particulars relevant to the claim ;
- relief claimed.

(2) Every intimation shall be duly signed and verified by the mortgagee, or the person holding the charge, lien or other interest or by a person duly authorised by him.

(3) Intimation may be filed in the office of the Commissioner at Calcutta or Bombay on all working days during office hours or may be sent to the Commissioner by registered post with acknowledgement due.

[File No. IME-49(10)/81]

MANISH BAHL, Jt. Secy.